

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने का नरिणय

प्रलिमिंस के लयि:

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने का नरिणय, वृद्धशील नकद आरकषति अनुपात (I-CRR), वैधानकि तरलता अनुपात [मौद्रकि नीति](#), [भारतीय रजि्रव बैंक](#)

मेन्स के लयि:

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने का नरिणय, इसकी आवश्यकता और नहितारथ

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में भारतीय रजि्रव बैंक (RBI) ने [वृद्धशील नकद आरकषति अनुपात \(I-CRR\)](#) को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की।

- केंद्रीय बैंक कई चरणों में I-CRR के तहत बैंकों द्वारा रखी गई राशाजारी करेगा।

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने की प्रक्रया:

- सुचारु परविरतन सुनश्चिति करने और **ससि्टम की तरलता में अचानक झटके को रोकने के लयि** I-CRR को बंद करने का कार्य **चरणबद्ध तरीके से कया जाएगा**।
 - I-CRR रविरसल के पहले और दूसरे चरण में प्रत्येक बैंक की जबत धनराशािका 25% जारी कया जाएगा। शेष 50% राशाितीसरे चरण में जारी की जाएगी।
- इस दृषटकिण का उद्देश्य यह सुनश्चिति करना है **कबैंकों के पास आगामी त्रयोहारी सीज़न के दौरान बढ़ी हुई ऋण मांग को पूरा करने के लयि पर्याप्त तरलता हो**।

I-CRR:

- पृष्ठभूमि:**
 - 10 अगस्त, 2023 को [मौद्रकि नीति](#) की घोषणा एवं 2000 रुपए के नोटों के [वमिद्रीकरण](#) के बाद RBI ने घोषणा की कबैंकों को अपनी [शुद्ध मांग और समय देनदारयिों \(Net Demand and Time Liabilities- NDTL\)](#) में वृद्धपरि 10 प्रतिशत का [वृद्धशील नकद आरकषति अनुपात \(I-CRR\)](#) बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
 - NDTL एक बैंक (सार्वजनकि या अन्य बैंक के पास) की मांग और समय देनदारयिों (जमा) तथा अन्य बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति के रूप में जमा के बीच का अंतर है।**
 - कहा गया कविह सतिंबर 2023 या उससे पहले इसकी समीक्षा करेगा।
- I-CRR शुरू करने का उद्देश्य:**
 - RBI ने बैंकिग प्रणाली में **अतरिकित तरलता को प्रबंधति** करने के लयि एक अस्थायी उपाय के रूप में I-CRR की शुरुआत की।
 - अधशेष तरलता** में कई कारकों ने योगदान दिया, जसिमें 2,000 रुपए के नोटों का वमिद्रीकरण भी शामिल है।
 - RBI द्वारा अधशेष सरकार को हस्तांतरति करना, **सरकारी खर्च और पूंजी प्रवाह में वृद्धिकरता है।**
 - इस तरलता वृद्धि में **मूल्य स्थरिता और वतितीय स्थरिता को बाधति करने की क्षमता थी**, जसिके लयि कुशल तरलता प्रबंधन की आवश्यकता थी।
- तरलता स्थतियिों पर I-CRR का प्रभाव:**
 - I-CRR उपाय बैंकिग प्रणाली से **1 लाख करोड रुपए से अधिक की अतरिकित तरलता** को अवशोषति करेगा।
 - I-CRR जनादेश के परणामस्वरूप **21 अगस्त, 2023 को बैंकिग प्रणाली की तरलता अस्थायी रूप से घाटे में बदल गई**, जो कविस्तु एवं

सेवा कर (GST) से संबंधित बहर्वाह और रुपए को स्थिर करने के लिये केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से बढ़ गई।

नकद आरक्षति अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR):

परिचय:

- बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले रज़िर्व में रखी जाने वाली नकदी का प्रतशित CRR कहलाता है।
- भारत में सभी बैंक (सभी अनुसूचित वाणजियिक बैंक (SCB) (RRB सहित), लघु वित्त बैंक (SFB), भुगतान बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB), राज्य सहकारी बैंक (STCB) और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को RBI के साथ CRR बनाए रखना होगा।
- प्रत्येक सहकारी बैंक (अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं) और स्थानीय क्षेत्र बैंक अपने पास या RBI के पास CRR बनाए रखेंगे।
- बैंक CRR की राशि को कॉरपोरेट्स या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते हैं, बैंक उस राशि का उपयोग नविश उद्देश्यों के लिये नहीं कर सकते और बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त करते हैं।

नोट: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ वर्ष 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं और RBI द्वारा विनियमित नहीं हैं

RBI के पास आरक्षति नकदी की आवश्यकता:

- चूँकि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा RBI के पास होता है, इसलिये यह किसी भी आपात स्थिति में राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- जब ग्राहक अपनी जमा राशि वापस चाहते हैं तो नकदी तुरंत उपलब्ध होती है।
- CRR मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का खतरा है, तो RBI द्वारा CRR बढ़ाया जाता है, ताकि बैंकों को रज़िर्व में अधिक धन रखने की आवश्यकता हो, जिससे बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा प्रभावी रूप से कम हो जाती है।
 - इससे अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह पर अंकुश लगता है।
- जब बाज़ार में धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो RBI, CRR दर कम कर देता है, जिससे बैंकों को नविश उद्देश्यों के लिये बड़ी संख्या में व्यवसायों और उद्योगों को ऋण प्रदान करने में मदद मिलती है। कम CRR से अर्थव्यवस्था की वकिस दर को भी बढ़ावा मिलता है।
- CRR और अन्य मौद्रिक साधनों को बनाए रखने की आवश्यकता हर वाणजियिक बैंक को होती है, लेकिन NFBC को नहीं।

वमिद्रीकरण के मामले में RBI द्वारा I-CRR का उपयोग:

- RBI ने अचानक तरलता में वृद्धि की स्थिति के लिये I-CRR को लागू करने का विकल्प चुना है, जैसे वमिद्रीकरण के दौरान।
 - RBI ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के बैंक नोटों के वमिद्रीकरण के बाद नवंबर 2016 में I-CRR का उपयोग किया था।
- यह RBI को मौद्रिक नीति के अन्य पहलुओं को प्रभावित किये बिना मुद्दे का समाधान करने की अनुमति देता है। यह सटीकता महत्त्वपूर्ण हो सकती है, खासकर वमिद्रीकरण जैसी अनोखी स्थितियों के दौरान।
- I-CRR को अपेक्षाकृत तेज़ी से लागू किया जा सकता है। जब वमिद्रीकृत नोटों की वापसी जैसी बड़े पैमाने की घटना के कारण तरलता में अचानक वृद्धि होती है, तो केंद्रीय बैंक को एक उपकरण की आवश्यकता हो सकती है जिसे तुरंत प्रभाव में लाया जा सके।
- I-CRR आमतौर पर एक अस्थायी उपाय माना जाता है। इसे तब शुरू किया जा सकता है जब अतिरिक्त तरलता को अस्थायी रूप से अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और तरलता की स्थिति स्थिर होने पर इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है।
- लेकिन दूसरी ओर अन्य उपकरण जैसे रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) आदि का तरलता पर दीर्घकालिक तथा धीमा प्रभाव हो सकता है।

RBI के मौद्रिक नीति उपकरण:

गुणात्मक:

- नैतिक दबाव:** यह एक गैर-बाध्यकारी तकनीक है जहाँ RBI बैंकों के ऋण और नविश व्यवहार को प्रभावित करने के लिये अनुनय एवं संचार का उपयोग करता है।
- प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण:** ये ऐसे उपाय हैं जिनमें वशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों के लिये ऋण के प्रवाह को विनियमित करना शामिल है। RBI नीतित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ क्षेत्रों को ऋण देने का निर्देश जारी कर सकता है या ऋण सीमा निर्धारित कर सकता है।
- चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण:** ये प्रत्यक्ष क्रेडिट नियंत्रण से अधिक वशिष्ट हैं और अर्थव्यवस्था के वशिष्ट क्षेत्रों में मांग को नियंत्रित करने के लिये उपभोक्ता ऋण जैसे विशेष प्रकार के ऋणों को लक्षित करते हैं।

मात्रात्मक:

- नकद आरक्षति अनुपात (CRR):** CRR किसी बैंक की जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उसे नकदी के रूप में RBI के पास आरक्षित रखना होता है। CRR को समायोजित करके RBI बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये उपलब्ध धन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है।
- रेपो दर:** रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रज़िर्व बैंक वाणजियिक बैंकों को अल्पावधि के लिये पैसा उधार देता है। रेपो दर में

बदलाव किये जाने से इन बैंकों की उधार लेने की लागत और उसके बाद उनकी उधार दरों पर असर पड़ सकता है।

- **रविर्स रेपो दर:** यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रख सकते हैं। यह अल्पकालिक ब्याज दरों के लिये एक आधार प्रदान करने के साथ ही तरलता प्रबंधन में मदद करता है।
- **बैंक दर:** वह दर है जिस पर RBI बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। यह दीर्घकालिक मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
- **ओपन मार्केट ऑपरेशंस:** इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार में सरकारी प्रतभूतियों की खरीद अथवा बिक्री करता है। यह बैंकिंग प्रणाली में धन आपूर्ति और तरलता को प्रभावित करती है।
- **तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF):** इसमें रेपो दर और रविर्स रेपो दर शामिल है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के लिये किया जाता है। यह RBI को प्रतिदिन तरलता स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
- **मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (MSF):** वह दर जिस पर बैंक सरकारी प्रतभूतियों के संपार्षक के लिये RBI से तुरंत ही ऋण ले सकते हैं। यह बैंकों के लिये वित्तपोषण के द्वितीयक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio- SLR):** यह किसी बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों का प्रतिशत है जिससे अनुमोदित प्रतभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षी अनुपात में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है? (2010)

- (a) वाणज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिये पैसे कम होंगे।
- (b) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उधार देने के लिये पैसे कम होंगे।
- (c) केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिये पैसे कम होंगे।
- (d) वाणज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिये पैसे अधिक होंगे।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा शब्द सरकार को ऋण प्रदान करने के लिये वाणज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले तंत्र को दर्शाता है? (2010)

- (a) नकद ऋण अनुपात
- (b) ऋण सेवा दायित्व
- (c) तरलता समायोजन सुविधा
- (d) वैधानिक तरलता अनुपात

Ans: (D)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजिये: (2015)

1. बैंक दर
2. खुला बाज़ार परचालन
3. सार्वजनिक ऋण
4. सार्वजनिक राजस्व

उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीतिका/के घटक है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: C

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'खुला बाज़ार परचालन' कसिे नरिदषिट करता है? (2013)

- (a) अनुसूचति बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना।

- (b) वाणज्यिकि बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना ।
(c) RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय ।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: C

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से सांवाधिकि आरक्षणि आवश्यकताओं का/के उद्देश्य है/हैं? (2014)

1. केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा नरिमति की जा सकने वाली अग्रमि राशियों पर नरियंत्रण रखने की सकषमता प्रदान करना ।
2. बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षणि व तरल रखना ।
3. व्यावसायिकि बैंकों को अत्यधिकि लाभ कमाने से रोकना ।
4. बैंकों को दनि-प्रतदिनि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोषठ नकदी (वॉल्ट कैश) रखने को बाध्य करना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कसकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) की स्थायी संवृद्धि तथा नमिन मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तरकों के समर्थन में कारण दीजिये । (2019)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-to-discontinue-i-crr>

